RAJHIN/2014/55262

sancharjagat.com

संचार जगत

दैनिक समाचार पत्र

sancharjagat.com | editorial@sancharjagat.com



'सोच को इतना बड़ा रखो कि असफलता भी एक छोटा कदम लगे। सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक दिशा है। बड़ा सोचो, बड़ा करो।'

वर्ष: 13 | अंक: 293 | जयपुर, गुरूवार, 26 नवम्बर 2026 | मूल्य: 2.00 रूपए | पृष्ठ : 4

पहली बार 'मां' बनीं मिस यूनिवर्स, जेनिफर बैरेटो ने रचा इतिहास

प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो की है सात साल की बेटी, पहले कभी ब्यूटी पेजेंट में नहीं लिया था भाग

नई दिल्ली/संचार जगत

मिस यूनिवर्स 2026 का ताज प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने अपने नाम कर लिया है। 75वें मिस यूनिवर्स में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में डोमिनिकन रिपब्लिक की मेलिसा नुनेज पहली रनर-अप रहीं, जबकि वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज ने दूसरे रनर-अप का स्थान हासिल किया।

फाइनल राउंड में प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेनेजुएला, फिलीपींस और न्यूजीलैंड की प्रतिभागियों ने जगह बनाई थी, जहां सभी से एक ही सवाल पूछा गया था कि मौजूदा समय में दुनिया को अपने नेताओं से सबसे ज्यादा क्या चाहिए। जेनिफर बैरेटो ने अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रभावशाली जवाब से जजों का दिल जीतते हुए मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। जेनिफर बैरेटो की जीत को और भी खास बनाने वाली बात ये है कि वो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली मां बनी हैं। जेनिफर शादीशुदा हैं और उनकी सात साल की बेटी पेनेलोप है। ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के साथ-साथ जेनिफर ने शिक्षा और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में भी उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री प्राप्त की है, वहीं साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में दो अलग-अलग मास्टर डिग्रियां भी हासिल की हैं। ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में कदम रखने से पहले जेनिफर बैरेटो अमेरिका के टेक्सास स्थित फोर्ट कैवाजोस में यूएस आर्मी फैमिली एडवोकेसी प्रोग्राम के साथ काम करती थीं।



कौन हैं जेनिफर बैरेटो

जेनिफर बैरेटो शादीशुदा हैं और उनकी सात साल की बेटी पेनेलोप है। ब्यूटी क्वीन होने के साथ-साथ जेनिफर पढ़ाई और सोशल वर्क में भी काफी आगे हैं। उन्होंने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उनके पास साइकोलॉजी और क्लिनिकल सोशल वर्क में दो मास्टर डिग्रियां भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, बैरेटो अमेरिकी रक्षा विभाग के आर्मी डिवीजन में प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती हैं। उनका काम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार से दूर रखने और बेहतर समुदाय बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाना है। उन्हें ट्रॉमा, बच्चों की सुरक्षा और घरेलू हिंसा की रोकथाम जैसे क्षेत्रों में भी काम करने का अनुभव है। इसके अलावा वह प्यूर्टो रिको की पीडियाट्रिक डायबिटीज एसोसिएशन के साथ वालंटियर के तौर पर जुड़ी हैं। यहां वह डायबिटीज से जूझ रहे बच्चों और उनके परिवारों की मदद करने के साथ इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाती हैं। इन सबके के अलावा खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और वॉलीबॉल खेलना पसंद है।

प्यूर्टो रिको ने अब तक 6 बार जीता है खिताब

जेनिफर बैरेटो की मिस यूनिवर्स 2026 में जीत के साथ प्यूर्टो रिको ने अब तक छह बार मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले मैरिसोल मलारेट (1970), डेबोरा कार्थी-ड्यू (1985), दयानारा टोरेस (1993), डेनिस क्यूनोनेस (2001) और जुलेयका रिवेरा (2006) ताज जीत चुकी हैं। खास बात ये है कि ये प्यूर्टो रिको की मेजबानी में मिला दूसरा मिस यूनिवर्स खिताब है। इससे पहले साल 2001 में, जब प्रतियोगिता प्यूर्टो रिको में आयोजित हुई थी, तब डेनिस क्यूनोनेस को विजेता घोषित किया गया था। मिस यूनिवर्स 75 का ग्रैंड फिनाले प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिजियम में आयोजित किया गया। ये कॉम्पटीशन इंटरनेशनल ब्यूजी पेजेंट के 75 साल पूरे होने का स्पेशल मौका भी था। इस साल इसमें 116 कंटेस्टेंट ने हिस्सा लिया। कॉम्पटीशन के दौरान कंटेस्टेंट्स ने नेशनल कॉस्ट्यूम, प्रीलिमिनरी और फाइनल राउंड में अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया।

भूपसेड़ा हत्याकांड में न्याय की गुहार पीड़ित परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा

संचार जगत

कोटपूतली-बहरोड़। एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर उस समय हड़कंप मच गया, जब पीड़ित परिवार के सदस्य एक कांग्रेसी नेता के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए। घटना बानसूर क्षेत्र के भूपसेड़ा गांव की है जहां पिछले दिनों हुई एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे। इस मामले में भूपसेड़ा गांव के ही एक भाजपा नेता पर महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के गंभीर आरोप लगे थे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले में उचित न्याय और सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी से आहत होकर पीड़ित परिवार के पिता-पुत्र एक कांग्रेसी नेता के साथ कलेक्टर कार्यालय के बाहर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए।

असम में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में आई कमी

संचार जगत



गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 2021 से 2025 के बीच असम में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामलों में 91.2 प्रतिशत की कमी आने का दावा किया है। उन्होंने इसे राज्य को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी प्रगति बताया। सरमा ने सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों को साझा करते हुए कहा कि दर्ज मामलों में कमी यह दर्शाती है कि राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने की दिशा में प्रगति की है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि हर महिला के लिए एक सुरक्षित असम बनाना हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम हर दिन काम करते हैं। महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में आई कमी हमारी प्रगति को दर्शाती है।

▶ जम्मू-कश्मीर के डीजीपी का एक्स पर बड़ा खुलासा

जम्मू के रहने वाले लापता 30 आतंकी पाक में ले रहे हैं ट्रेनिंग, हुई पहचान

हिज्बुल मुजाहिदीन के लिए कर रहे हैं काम, भारत में फैलाना चाह रहे दहशत

नई दिल्ली/संचार जगत



जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के 30 आतंकवादी 1991 से 2003 के बीच गायब हो गए, अब उनके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि वे पाकिस्तान चले गए हैं।

वे वहां एक आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फिर से पैर जमाने के मकसद से हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया करा रहे हैं। यह दावा पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बुधवार को यह दावा किया है। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि महोर पुलिस थाने को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि महोर और चसाना के रहने वाले 30 आतंकवादी भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान चले गए थे। ये सभी आतंकी 1991 से 2003 के बीच लापता हो गए थे। डीजीपी ने एक्स पर आधिकारिक हैंडल पर लिखा, ये लोग अब पाकिस्तान में एचएम (हिज्बुल मुजाहिदीन) के लिए काम कर रहे हैं। वे जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया करा रहे हैं, साथ ही युवाओं को उकसाकर और कट्टर बनाकर उन्हें इस इलाके में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

वापस लौटे 5 की हुई पहचान

डीजीपी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए और पांच संदिग्ध आतंकियों की पहचान की। ये लोग हथियारों और गोला-बारूद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान चले गए थे और सीमा पार से इस इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिशों में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके लिए उन्होंने आतंकवाद को फंड देने के मकसद से अपनी जमीनें बेच दी थीं। इनकी पहचान महोर तहसील के शाडोल निवासी मो. कय्यूम (उर्फ अब्दुल कय्यूम), बिडर निवासी बशीर अहमद (उर्फ मासूम), अरनास तहसील के हुंडर निवासी शौकत अली, थुरू तहसील के खंती निवासी मंजूर अहमद (उर्फ मंजूर हुसैन) और थुरू निवासी इम्तियाज अहमद के रूप में हुई है। पुलिस ने रियासी के इन पांच आतंकवादियों की 27 कनाल से अधिक जमीन भी जब्त कर ली है।

माइनिंग ब्लॉक्स के ऑक्शन में राजस्थान अव्वल

संचार जगत



जयपुर। सचिवालय में खान विभाग के अंतरविभागीय प्रकरणों से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने खान विभाग द्वारा मेजर और माइनर ब्लॉकों के ऑक्शन में तेजी और नीलाम खानों को परिचालन में लाने के विभागीय प्रयासों की सराहना की है। बैठक में वी. श्रीनिवास ने अरावली जिलों को छोड़कर अन्य स्थानों पर मिनरल एक्सप्लोरेशन और माइनिंग ब्लॉकों पर फोकस करने पर जोर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में ही अब तक 24 मेजर मिनरल ब्लॉकों का ऑक्शन कर राजस्थान समूचे देश में मेजर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन में अव्वल आ गया है। उन्होंने संबंधित विभागों से परस्पर समन्वय व संवाद बनाकर अन्तरविभागीय मुद्दों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इससे प्रदेश में खनिज क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से निवेश, रोजगार और राजस्व के नए अवसर विकसित होंगे। बैठक में सीया, वन, नगरीय विकास, राजस्व और परिवहन विभाग से माइंस विभाग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नीलाम खानों को परिचालन में लाने में भी हमें समूचे देश में अग्रणी प्रदेश बनना है, इसके लिए आवश्यक अनुमतियां जारी करने और खनन कार्य आरंभ कराने के लिए संबंधित विभागों को एक्शन मोड़ पर आगे आना होगा।

सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत

संचार जगत



बहरोड़। बहरोड़ में हुए सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई। हादसा जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग-48 मंगलवार देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे डंपर के चालक ने बिना कोई संकेत दिए अचानक सड़क के बीच में वाहन रोक दिया। इससे पीछे आ रही कार डंपर में घुस गई। हादसे के बाद पांचों घायलों को उपचार के लिए पार्क अस्पताल बहरोड़ ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल हरीश कुमार को अलवर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पांचों दोस्त चचेरे भाइयों की शादी समारोह से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान दहमी पुलिया के पास उनकी कार आगे चल रहे डंपर में पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया।

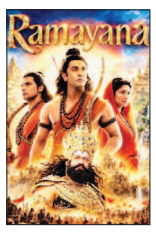
उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत

संचार जगत



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, दोनों की ओर से दायर जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में खालिद और इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर जल्द विचार करने का आग्रह किया। सिब्बल ने कहा कि वह छह साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत की मांग पर विचार करने से पहले वह दूसरे पक्ष दिल्ली पुलिस की बात सुनेगी। गौरतलब है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम छह साल से अधिक समय से जेल में हैं।

रामायण ने ऑस्कर की दहलीज पर दी दस्तक



नई दिल्ली / आरएनएन। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म रामायण अपनी भव्यता और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के लिए चर्चा बटोर रही है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसके वीएफएक्स की खूब तारीफ हो रही है। अब यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड्स के मंच पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है। पहले 32वें क्रिटिक्स च्वाइस अवॉर्ड्स की दो कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होने के बाद अब फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रामायण ने 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर की विजुअल इफेक्ट्स कैटेगरी में टॉप 20 फिल्मों की सूची में जगह बनाई है।

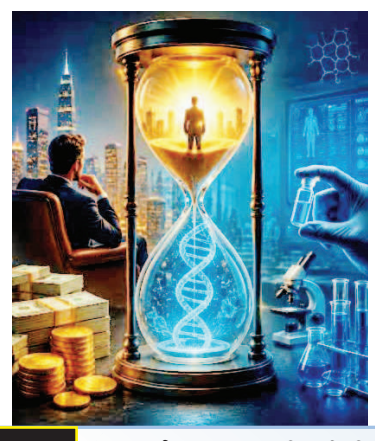
स्टडी | भारत में लोगों के जीवित रहने की संभावना पर घरेलू संपत्ति का असर जाति और धर्म से भी ज्यादा

अमीर पुरुषों में जल्दी मौत का जोखिम 62 प्रतिशत कम

नई दिल्ली/संचार जगत

भारत में अमीर और गरीब लोगों की मृत्यु दर में बड़ा अंतर सामने आया है। एक नई स्टडी में सामने आया है कि देश के सबसे अमीर परिवारों में रहने वाले पुरुषों की कामकाजी उम्र के दौरान मौत होने का खतरा सबसे गरीब परिवारों के पुरुषों के मुकाबले 62 फीसदी कम है।

महिलाओं के मामले में भी यह अंतर काफी बड़ा है। अमीर परिवारों की महिलाओं में गरीब परिवारों की महिलाओं के मुकाबले मौत का जोखिम 42 फीसदी कम पाया गया है। यह स्टडी बताती है कि भारत में 15 से 59 साल की उम्र के लोगों के जीवित रहने की संभावना पर घरेलू संपत्ति का असर जाति और धर्म से भी ज्यादा है। हालांकि, इसके बावजूद कुछ सामाजिक समूहों में मौत का खतरा अधिक बना हुआ है। खासतौर पर अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं में अगड़ी जाति की हिंदू महिलाओं के मुकाबले मौत का जोखिम ज्यादा पाया गया। वहीं, मुस्लिम पुरुषों में अगड़ी जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में मृत्यु का जोखिम कम दर्ज किया गया। यह रिसर्च डेमोग्राफिक रिसर्च नाम के पीयर-रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हुई है।



मुस्लिम पुरुषों में कम मृत्यु दर

इस स्टडी का एक अहम निष्कर्ष मुस्लिम पुरुषों की मृत्यु दर से जुड़ा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि तीनों सर्वे के दौरान मुस्लिम पुरुषों में अगड़ी जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में वयस्क उम्र में मौत का जोखिम लगातार कम रहा। 2019-21 के आंकड़ों के मुताबिक, घरेलू संपत्ति, रहने की जगह और राज्य के अंतर को ध्यान में रखने के बाद भी मुस्लिम पुरुषों में अगड़ी जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में मौत का जोखिम 21 फीसदी कम था। शोधकर्ताओं ने इसके पीछे कुछ संभावित वजहों का जिक्र किया है। उनके मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के वयस्कों में शराब का सेवन कम होना और कई राज्यों में मुस्लिम आबादी का शहरी इलाकों में ज्यादा रहना इसकी संभावित वजहें हो सकती हैं। शहरी इलाकों में रहने से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर हो सकती है।

जाति के आधार पर भी सामने आया अंतर

स्टडी में जाति के आधार पर मृत्यु दर में अंतर भी देखा गया। इसके मुताबिक, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पुरुषों में अगड़ी जाति के हिंदू पुरुषों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा थी। हालांकि, शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अंतर के पीछे उनकी आर्थिक स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी वजह हो सकती हैं। 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति के पुरुषों में मृत्यु की संभावना प्रति 1,000 लोगों पर 256 थी। वहीं, अनुसूचित जनजाति के पुरुषों में यह आंकड़ा 254 था। इसकी तुलना में अगड़ी जाति के हिंदू पुरुषों में यह संख्या 197 दर्ज की गई। महिलाओं के मामले में भी सामाजिक अंतर देखने को मिला। स्टडी के मुताबिक, आर्थिक स्थिति और रहने की जगह जैसे कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी अनुसूचित जाति की महिलाओं में अगड़ी जाति की हिंदू महिलाओं के मुकाबले वयस्क उम्र में मौत का जोखिम 19 फीसदी ज्यादा था।

अब एक यूएन से जुड़ सकेंगे कई एम्प्लॉयर

क्लेम सेटलमेंट भी होगा तेज

नई दिल्ली/संचार जगत



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अब तक के सबसे बड़े टेक बदलावों में से एक की तैयारी कर रहा है। इसके तहत फरवरी 2027 तक ईपीएफओ 3.0 को लॉन्च किए जाने की संभावना है।

उम्मीद है कि इस नए सिस्टम से प्रोविडेंट फंड (पीएफ) सेवाएं तेज हो जाएंगी, पैसे निकालना आसान हो जाएगा और पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी स्ट्रक्टर से बाहर काम करने वाले लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिल सकेगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, इन बदलावों का मतलब है कि वे अपनी रिटायरमेंट बचत तक आसानी से पहुंच सकेंगे, उन्हें ईपीएफओ दफ्तरों के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे और उनके क्लेम का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा।

ईपीएफओ ने पीएफ मैनेज करने का तरीका बदलेगा

संपादकीय

सफलता का संदेश या विफलता का संकेत

हर शब्द का एक भाव होता है, उसका संकेत होता है और संदेश भी। इसलिए मन के भावों की अभिव्यक्ति में जो संदेश छिपा होता है, उसका मतलब समझना जरुरी होता है। हर भावना और विचार को सीधे तरीके से नहीं कहा जाता और सकता है। कभी कभी उपमाओं, लोकोक्तियों और मुहावरों से भी उस विचार को सहज और सरल तरीके से कह दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की वार्षिक आम सभा में उद्योग जगत के सामने अपने मन की बात को जिस अंदाज में उजागर किया, उसके कई मायने हैं। अगर बात आसान होती तो हर किसी को सहज ही समझ में आ जाती, लेकिन माया के मोह में रमने वाले कुबेरों को उसके मायने को समझने में दिल और दिमाग दोनों की जरुरत होगी। बात छोटी सी थी लेकिन जिस सहज अंदाज में नरेन्द्र मोदी ने उनके सामने कही, वह विकास की दिशा में आगे बढ़ने वाली व्यवस्था में विसंगतियों को उजागर करने के लिए काफी थी। और खास बात यह कि किसी ने भी उनकी बात को हल्के में नहीं लिया, और वह विषय गंभीरता से सोचने और आत्म चिंतन के अवसर में बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री यानी फिक्की की वार्षिक आम सभा में विकसित भारत की परिकल्पना का चित्रण करते हुए कहा कि भारत की अगली बड़ी छलांग की शुरुआत ईमानदार आत्ममंथन से होनी चाहिए। इसके लिए उद्योग जगत से अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने की अपील की। सलाह और सुझाव के साथ ही, उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को एक तीखा और दो टूक संदेश देते हुए रोजगार सृजन, वेतन वृद्धि, निवेश और नई क्षमताओं के विकास के मोर्चे पर पर्याप्त प्रयास न करने के लिए आड़े हाथों लिया। उनके मुताबिक इन क्षेत्रों में उद्योग जगत की नाकामी ने भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने की राह में बाधा पैदा की है। मोदी ने कारोबारी जगत की उस प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाए जिसमें वह एक संरक्षित घरेलू बाजार के सहारे अल्पकालिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है। इसमें कॉरपोरेट आयकर में कटौती और सीमा शुल्क के जरिये संरक्षण देने से लेकर व्यक्तिगत आयकर तथा माल एवं सेवा कर में कटौती और नए व्यापार समझौतों के माध्यम से मांग पैदा करने की उम्मीदें शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने फिक्की के सदस्यों को याद दिलाया कि संगठन अपने गठन का 100वां वर्ष मना रहा है और वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने भी उद्योग जगत को लगभग यही संदेश दिया था। उन्होंने उद्योग जगत से पूछा कि आत्मनिर्भरता की जरूरत को दोबारा रेखांकित करने की उनकी आवश्यकता क्या की सफलता का संकेत है या उसकी विफलता का? 2025-26 की आर्थिक समीक्षा में इस बात को रेखांकित किया गया था कि वेतन और रोजगार में वृद्धि, कॉरपोरेट मुनाफे में हुई बढ़ोतरी के मुकाबले काफी पीछे रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट मुनाफा 15 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।



बदलती दुनिया में साझा लक्ष्य, सहयोग और संतुलन

लेकिन आगे क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कई लोगों ने इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की थी, जिसमें रूस के नेता जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विश्वयुद्ध के बाद के यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। लेकिन शेंझेन शिखर सम्मेलन किसी बड़े युद्ध के विजेताओं का सम्मेलन नहीं था। यह एक बदलती दुनिया में तीन बड़ी ताकतों के बीच आपसी संबंधों के नियम तय करने जैसा था। यह शिखर सम्मेलन एजेंडे में शामिल किसी भी मुद्दे, मसलन परमाणु हथियारों में कटौती, हथियारों के प्रसार को रोकना या यूक्रेन युद्ध, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल सका और न ही भविष्य का कोई स्पष्ट खाका दे पाया।



तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिक्स में हर देश की भूमिका बदलती जा रही है। खास कर कई देशों के बीच संघर्ष, युद्द के हालात, तनाव और उपजे हालातों में बुरी तरह प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्थाएं। ये चुनौतियां किसी एक देश के साथ होती तो उसे समझा जा सकता है, लेकिन आज किसी दो देशों के बीच की टकराहट से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, ऐसा देखा और समझा जा रहा है। यही कारण है कि विश्व के छोटे देश, अल्प और अर्ध विकसित देश और विकासशील देशों के सामने आ रही चुनौतियां और उससे जूझने की कसमसाहट ने हर किसी को हतप्रभ कर दिया है।

इतना ही नहीं, खुद के मकड़जाल में फंसे विकसित कहे जाने वाले देश भी छटपटा रहे हैं। भरोसे के संकट ने उनकी दुविधा को और अधिक बढ़ा दिया है। इसलिए हर कोई देश हर स्तर पर सहज, सरल और अनुकूल परिस्थितियों बनाने के लिए प्रयास करता नजर आ रहा है। 19 नवंबर को शेंझेन में चीन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच हुआ पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन, बदलती वैश्विक व्यवस्था और एक तेजी से अनिश्चित होती दुनिया में एक-दूसरे के साथ जुड़े रहने की इन नेताओं की साझा इच्छा को दर्शाता है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, यह शिखर सम्मेलन एक ऐसा मंच था जहां वे परमाणु हथियारों को कम करने के लिए दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों के बीच संयुक्त वार्ता पर जोर दे सकते थे। इस साल फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि की मियाद खत्म होने के बाद, मॉस्को ने संकेत दिया था कि वह बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ट्रम्प इसमें चीन को भी शामिल करना चाहते थे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिहाज से, इस शिखर सम्मेलन ने अमेरिका के बराबर के प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन की स्थिति को और मजबूत किया। जहां रूस चीन के साथ अपनी साझेदारी को गहरा करना चाहता है, वहीं अमेरिका रणनीतिक स्थिरता कायम करने की कोशिश कर रहा है।

और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों ने अलग-थलग करने की कोशिश की थी, के लिए यह शिखर सम्मेलन एक अहम मंच पर जगह पाने का मौका लेकर आया। परमाणु हथियारों पर त्रिपक्षीय बातचीत शुरू करने का फैसला और वह संयुक्त घोषणा, जिसमें यह कहा गया है कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और इसे कभी लड़ा भी नहीं जाना चाहिए, सही दिशा में उठाए गए कदम हैं।

लेकिन आगे क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। कई लोगों ने इस बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से की थी, जिसमें रूस के नेता जोसेफ स्टालिन, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विश्वयुद्ध के बाद के यूरोप के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी। लेकिन शेंझेन शिखर सम्मेलन किसी बड़े युद्ध के विजेताओं का सम्मेलन नहीं था। यह एक बदलती दुनिया में तीन बड़ी ताकतों के बीच आपसी संबंधों के नियम तय करने जैसा था। यह शिखर सम्मेलन एजेंडे में शामिल किसी भी मुद्दे, मसलन परमाणु हथियारों में कटौती, हथियारों के प्रसार को रोकना या यूक्रेन युद्ध, पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल सका और न ही भविष्य का कोई स्पष्ट खाका दे पाया। इसके अलावा, यह भी साफ नहीं है कि शेंझेन की भावना' मध्यम से लंबी अवधि तक बनी रह पाएगी या नहीं, क्योंकि अमेरिका में आने वाला कोई नया राष्ट्रपति रूस और चीन के प्रति बिल्कुल अलग रुख अपना सकता है।

तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान किया है। यूं तो यह एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एवं संस्थानों में सुधार की किसी भी कोशिश में अन्य ताकतों को भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसी उभरती हुई मध्यम स्तर की शक्तियों को। फिर भी, शेंझेन का ढांचा बड़ी ताकतों के आपसी संबंधों में ज्यादा स्थिरता और निश्चितता ला सकता है।

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन तीन बड़ी ताकतों में से दो अभी अलग-अलग युद्धों में उलझी हुई हैं। तीनों नेताओं को परमाणु वार्ता और शेंझेन घोषणापत्र में बताए गए अन्य अहम मुद्दों के लिए एक ऐसा स्पष्ट खाका तैयार करना चाहिए, जिसमें व्यावहारिक और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य हों। वरना, यह शिखर सम्मेलन महज दिखावे का एक और कूटनीतिक मजमा बनकर रह जाएगा।

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव ने ट्रम्प को दिखाया आईना

अमेरिका में हुए मध्यावधि चुनाव में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण खो देने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को अपने मौजूदा कार्यकाल का सबसे भारी राजनीतिक झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों ने न सिर्फ कोलोराडो, ओरेगॉन तथा इलिनोइस जैसे अपने पारंपरिक गढ़ वाले राज्यों में शानदार जीत हासिल की और जॉर्जिया, मिशिगन तथा वर्जीनिया जैसे महत्वपूर्ण निर्णायक राज्यों पर अपना कब्जा बरकरार रखा, बल्कि उन्होंने टेक्सास, कंसास तथा आयोवा जैसे रिपब्लिकन-बहुल राज्यों में भी ऐतिहासिक पैठ बनाई। चुनाव परिणाम के बाद ट्रम्प ने अपने दंभ को बनाए और बचाए रखते हुए कहा भी था कि अगर मतपत्रों पर उनका नाम होता, तो रिपब्लिकन पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता। वहीं वे इस हकीकत को भी कबूल करते नजर आए कि उनके कार्यकाल के बचे हुए दो सालों में उन्हें डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ मिलकर काम करना होगा। संघीय सरकार के भावी कामकाज पर पड़ने वाले तात्कालिक असर के



अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की लहर ने राज्य स्तर पर भी बड़े बदलाव किए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने 37 सालों में पहली बार टेक्सास में सीनेट की एक सीट जीती है। मिशिगन में जीत हासिल करने वाले डेमोक्रेट अब्दुल अल-सैयद इतिहास में पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं। न्यू हैम्पशायर के क्रिस पैपास सीनेट के लिए चुने जाने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति बन गए हैं। और सीनेट में अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफरीज जल्द ही सदन के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी स्पीकर हो सकते हैं।

यह विडंबना है कि ट्रम्प ने मतपत्रों पर अपना नाम नहीं होने को रिपब्लिकन पार्टी की हार की वजह बताया, जबकि कई मतदाताओं के लिए यह मध्यावधि चुनाव असल में ट्रम्प प्रशासन के कामकाज पर एक जनमत संग्रह ही था। रहन-सहन के खर्च, नौकरियां, आव्रजन संबंधी कदमों के अमल और ईरान युद्ध सहित ट्रम्प प्रशासन की प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताओं को लेकर मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से असहमति जताई है। दीवार पर लिखी इबारत बिल्कुल साफ थी और स्वीकार्यता रेटिंग भी यही हकीकत बयां कर रही थीं। खासकर, तेल की कीमतों और ईरान युद्ध के मामले में। दरअसल, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव बढ़ने के बाद से अमेरिका में गैस की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। इसी तरह, आईसीई द्वारा बड़े पैमाने पर की गई छापेमारी और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को देश से निकालने की अंधाधुंध प्रक्रिया के कारण कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन हुए और इसने प्रगतिशील लोगों को आव्रजन संबंधी सुधार के मुद्दे पर एकजुट कर दिया। ट्रम्पवाद के दो मुश्किल सालों के बाद मिली जीत का जश्न मनाना डेमोक्रेट्स के लिए भले ही सही हो, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस द्वारा पारित नीतियों पर वीटो का अधिकार अभी भी राष्ट्रपति के पास है। ट्रम्प के व्हाइट हाउस के कामकाज की जांच और पूछताछ करने का लोभ भले ही काफी प्रबल हो, फिर भी कांग्रेस के डेमोक्रेट सदस्य शायद ऐसे किसी भी दिखावे से बचना चाहेंगे जिसका कोई ठोस नीतिगत असर न हो। इसमें ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करना भी शामिल है। डेमोक्रेटिक सांसदों के लिए आगे बढ़ने का एक ज्यादा सार्थक तरीका यह होगा कि वे व्हाइट हाउस के साथ जुड़ें और बातचीत तथा समझौते के जरिए स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़ी बीमा और टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नुकसानदायक नीतियों के वास्तविक असर को कम करें।

मैदान में आते ही पहाड़ पिघल गया, भारत- नेपाल के रिश्ते

अथल-पुथल भरे भारत-नेपाल संबंधों में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दिल्ली दौरे को एक नई शुरुआत के मौके के रुप में देखा जा रहा है। पूर्व सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जेन ज़ी आंदोलन के नेता के तौर पर बालेंद्र शाह के सत्ता में आने के आठ महीने बाद यह यात्रा हुई। उनके पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली की सरकार के साथ मोदी सरकार के तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए, शाह को उनकी पहली राजकीय यात्रा पर भारत ला पाना खास तौर पर अहम माना जा रहा है। ओली को उनके एक साल से अधिक के कार्यकाल में दिल्ली नहीं बुलाया गया और वे इसके बजाय बीजिंग गये। शुरू में, बालेंद्र शाह सीमा विवादों पर अपनी टिप्पणियों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ बैठक पक्की करने से इनकार करके नयी दिल्ली को कुछ चिंताजनक पल दिये, जिसके चलते मई में उनका दौरा रद्द हो गया। बाद में, शासन चलाने से जुड़ी कुछ वास्तविकताओं ने, खास तौर पर अगस्त में आयी भीषण बाढ़ के पश्चात, दिल्ली और काठमांडू के संबंधों में गर्माहट ला दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बातचीत के बाद, बालेंद्र शाह ने बाढ़ राहत और बचाव अभियानों में तत्काल और भरपूर सहयोग के लिए भारत का शुक्रिया अदा



किया। मोदी द्वारा शाह की तारीफ से उनके बीच एक निजी दोस्ताना बनने का संकेत मिलता है, जिसके आधार पर संबंधों के लिए रोडमैप तैयार होगा। भारत ने नेपाल में पुनर्निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए एक विकास सहयोग पैकेज की घोषणा की, जो 15 हजार करोड़ रुपये का है। नेपाल को गुजरात और ओडिशा में भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच देने की एक अन्य घोषणा लैंड-लॉक्ड नेपाल की मदद में बहुत काम की साबित होगी, खासकर साल 2015 की व्यापार नाकेबंदी को लेकर दोनों देशों के बीच कड़वाहट को देखते हुए। पुलों, सड़कों, ट्रेनों, ऊर्जा और ईंधन लाइनों, एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के उद्घाटन, और एक आईआईटी स्थापित करने का समझौता, ये सब संकेत हैं संबंध सुधारने की ठोस योजनाओं के, जिनकी रूपरेखा विकसित भारत और समुन्नत नेपालः साझेदारी की नयी परिकल्पना शीर्षक वाले संयुक्त बयान में पेश की गयी है। संबंधों को लेकर कुछ तीखे बयानों के बावजूद, ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों ने अपने मतभेदों के विषयों को कम सार्वजनिक तरीके से सुलझाने का फैसला किया है।

गठबंधन के दौर में महत्वाकांक्षाओं की कसमसाहट

धीरे-धीरे चुनाव की ओर बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष सहज स्थिति में दिखाई दे रहा है तो विपक्ष के भीतर सीटों के बंटवारे पर वही पुरानी खींचतान शुरू हो गयी है। सीटों के तालमेल में उलझे विपक्ष को यह नहीं सूझ रहा है कि चुनाव की नैया को कैसे पार लगाया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक समझदारी बनी थी, जिससे राज्य की सीटों का अच्छा खासा हिस्सा उनकी झोली में आया था। लेकिन बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब 181 सीटें मांग रही है, जो कुल 403 विधानसभा क्षेत्रों का तकरीबन 45 फीसदी है। यह उस दुविधा का ताजातरीन उदाहरण है, जिससे कांग्रेस गुजर रही है। खासकर, उन राज्यों में जहां वह हाशिए पर पहुंच चुकी है और अपना पुनरुत्थान चाहती है। कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन को कमजोर किए बिना, अपने अपेक्षाकृत मजबूत सहयोगियों से अपने लिए फायदेमंद सौदेबाजी की जाए। यह देखते हुए कि भाजपा, जो अब भी दलीय व्यवस्था में दबदबे की स्थिति में है, के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है। विपक्ष को परिस्थितियां अपने अनुकूल लग रही हैं और इसके प्रमुख दल इस बात पर सहमत हैं कि भाजपा का मुकाबला करने का इकलौता तरीका एक ऐसा शक्तिशाली गठबंधन बनाना है, जिसका एक प्रबल और एकजुट संदेश हो। लेकिन हिंदी पट्टी और उन राज्यों में, जहां कभी कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, खुद को दोबारा खड़ा करने की उसकी कोशिशों से, गठबंधन की एकता दबावग्रस्त हो गयी है। बिहार में, महागठबंधन जनता दल यूनाइटेड-भाजपा गठबंधन के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर की फसल काटने में नाकाम रहा, आंशिक रूप से इसलिए कि वह राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के पीछे मौजूद सामाजिक ताकतों का पूरा समर्थन नहीं जुटा सका और आंशिक रूप से इसलिए भी कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे के निपटारे में इतना वक्त ले लिया कि चुनाव अभियान एकाकार नहीं हो पाए। तमिलनाडु में, कांग्रेस द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से और सीटों की मांग पर अड़ी रही और गठबंधन में देरी की, जबकि अंदरूनी कलह के कारण उसका चुनाव अभियान फीका रहा, जिसके चलते उसे, जिन सीटों पर वह लड़ी, सभी गठबंधन साझेदारों में सबसे कम वोट शेयर मिला।

उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस यदि इसी रास्ते पर चली तो उसके परिणाम क्या होंगे, यह उसके लिए सोचने की जरूरत है। दरअसल 181 सीटों की मांग उस पार्टी के लिए बहुत महत्वाकांक्षी है, जो साल 2022 में अपनी लड़ी 399 सीटों पर महज 2.33 फीसदी वोट पा सकी, जबकि सपा जिन 347 सीटों पर लड़ी उसमें से 111 पर जीत दर्ज की और 32 फीसदी वोट हासिल किए। कांग्रेस के लिए यह बात वाजिब हो सकती है, लेकिन गठबंधन के लिए भी यह देखना जरुरी है कि उसे किस सीमा तक जाना है। क्यूंकि लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक काफी चीजें बदली हैं। 2024 में, सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतीं। उन्हें 43.2 फीसदी वोट शेयर मिला, जो भाजपा-नीत गठबंधन के 43.7 फीसदी से थोड़ा ही कम था। कांग्रेस ने



जिन 17 सीटों पर लड़ा, उनमें से वह केवल छह सीटें जीत पाई, लेकिन इन छह पर उसका वोट शेयर 44.2 फीसदी रहा, जो सपा के 43.4 फीसदी से थोड़ा ज्यादा था। कांग्रेस लगातार यह दलील देती आ रही है कि युवाओं की चिंताओं और भारत के चुनावी लोकतंत्र की दशा पर उसके राष्ट्रीय अभियानों ने उसे ज्यादा मांगने लायक ताकत दी है। लेकिन एक सक्षम राज्यव्यापी संगठन का अभाव बताता है कि 181 बहुत ज्यादा है। सपा सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनी हुई है और उसने स्थानीय गोलबंदियों के जरिए बहुसंख्यकवादी भाजपा से मुकाबला करने के लिए पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक नया सामाजिक गठबंधन तैयार किया है।

भूखी-प्यासी गायों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

संचार जगत

सिरोही। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अलग ही नजारा देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में पशुपालक अपने साथ करीब 800 गायों को लेकर पहुंच गए। पशुपालकों का कहना था कि क्षेत्र में चारे और पानी का गंभीर संकट बना हुआ है। पशुपालक पशुओं के लिए चारा-पानी के संकट से परेशान हैं। वे करीब 800 गायों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। गायों के साथ पहुंचे पशुपालकों ने प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा रखी और जिले को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की। पहले एसडीएम के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इसके बाद जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर खुद



प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने कुर्सी पर बैठने के बजाय जमीन पर बैठकर पशुपालकों की बात सुनी। कलेक्टर का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। आखिरकार उनके आश्वासन के बाद पशुपालकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। पशुपालकों ने बताया कि जिले में करीब 20 हजार गायें चारा-पानी की कमी से प्रभावित हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। उनके अनुसार, उन्होंने करीब दो सप्ताह पहले भी प्रशासन को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें सैकड़ों गायों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करना पड़ा।

अगले विधानसभा चुनाव में फिर बनेगी भाजपा सरकारः मदन राठौड़

संचार जगत



जयपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जिला प्रमुख के चुनाव में 10 जिलों में पार्टी का जिला प्रमुख बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरी है, भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में और अधिक गति से राजस्थान की सेवा की जाएगी और 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को अपने उस झूठे प्रोपेगेंडा पर जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने परिसीमन पर झूठ बोला, ईवीएम को बदनाम किया, हमारी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ये सब अब जनता के समझ में आ गया है, इसलिए कांग्रेस को जनता से और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के परिणाम विधानसभा के चुनाव परिणाम नहीं होते। राठौड़ ने कहा कि अब तक हुए पंचायती राज चुनाव परिणामों के आधार पर भी ये बात साबित होती है कि पंचायती राज चुनावों में किसी पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती है। राजस्थान की जनता ने पांच साल के लिए हमें जो सेवा का अवसर दिया है, उसी के अनुरूप अगले दो वर्ष हम पूरी प्रमाणिकता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह अहंकार में न आए, भाजपा के कार्यकर्ता पूरी क्षमता से 2028 चुनाव में जवाब देंगे।

सचिन पायलट ने भाजपा-अकाली दल गठबंधन को मजबूरी का बताया

संचार जगत



जयपुर। पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा-अकाली दल के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन करार दिया। पायलट ने कहा कि पंजाब के लोग इस गठबंधन को सिरे से नकारेंगे। उनके अनुसार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होगा। पायलट ने जयपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गठबंधन एक मजबूरी का परिचय है। पंजाब में भाजपा की कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। पायलट ने कहा कि पंजाब के लोग इस गठबंधन को सीधे नकारेंगे। उनके अनुसार मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है। पायलट ने कहा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि भाजपा का सूपड़ा साफ हुआ है। लोगों ने भाजपा सरकार के कार्यकाल को आईना दिखाया है। लोग समझ चुके हैं

संतोष कुमारी निर्विरोध बनीं जिला प्रमुख



जैसलमेर। की राजनीति में एक युवा चेहरे ने ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है। महज 21 साल की उम्र में एक बेटी जिले की सबसे बड़ी पंचायती राज कुर्सी तक पहुंच गई। जैसलमेर की नई जिला प्रमुख बनीं संतोष कुमारी ने राजस्थान की सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख बनने का रिकॉर्ड कर लिया है। संतोष कुमारी जैसलमेर के पोकरण विधानसभा क्षेत्र से आती हैं।

उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद के वार्ड संख्या 21 से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने 6 हजार 208 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए समीक्षा बैठक

किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए करें जागरूक : वी. श्रीनिवास



संचार जगत

जयपुर। प्रदेश में रबी फसलों की बुवाई के दौरान किसानों को यूरिया एवं डीएपी की सुगम, समयबद्ध एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में 2026-27 के दौरान प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की मांग, आपूर्ति एवं जिलेवार उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों एवं उर्वरक कंपनियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में यूरिया एवं डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बुवाई के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी संबंधित विभाग एवं उर्वरक निर्माता कंपनियां समन्वित प्रयास करते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करें। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मासिक आवंटन के अनुरूप राज्य को आपूर्ति नहीं करने वाली कंपनियों के आवंटन में कटौती कर उसे बेहतर आपूर्ति करने वाली सक्षम कंपनियों को अंतरित करने के लिए कृषि विभाग केंद्र सरकार से समन्वय एवं पत्राचार करे।

बैठक में उर्वरकों के अवैध डायवर्जन, भंडारण एवं कालाबाजारी की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में संचालित अभियान की प्रगति से अवगत कराया गया।

राजस्थान में शीतलहर से बढ़ी सर्दी



संचार जगत

जयपुर। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के तेज होने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, टोंक, पिलानी और सीकर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान नीचे आया। उत्तर-पूर्वी राजस्थान के जिलों में सुबह और शाम हल्की शीतलहर चलने लगी है। इसका सबसे ज्यादा असर नागौर, सीकर, अलवर और अजमेर के आसपास के इलाकों में देखने को मिला। शेखावाटी क्षेत्र में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। सीकर के फतेहपुर में रात का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सीकर में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही फतेहपुर प्रदेश के सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा। दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में अभी सर्दी का असर अपेक्षाकृत कम है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह और शाम सर्दी का असर तेज रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और दिन में धूप निकलने का अनुमान है। हालांकि, उत्तरी हवाओं का असर जारी रहने से सुबह और रात के समय सर्दी से राहत मिलने की संभावना कम है।

राहुल गांधी को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश

संचार जगत



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिए। सीबीआई और ईडी जांच की मांग से जुड़े मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने और मामले में हुई प्रगति की जानकारी हाईकोर्ट को देने के निर्देश दिए गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। मामले की शुरुआत कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से हुई थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इन आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की थी। शिशिर ने अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इन दस्तावेजों और आरोपों की सत्यता अदालत या किसी जांच एजेंसी की ओर से अंतिम रूप से स्थापित नहीं की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मई 2026 में याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन करने और मामले में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने हाईकोर्ट के उन निर्देशों को चुनौती दी, जिनके तहत सीबीआई और ईडी को शिकायत का सत्यापन करने और अदालत को प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

जिला प्रमुख चुनाव के बीच हंगामा, भीलवाड़ा-भरतपुर में भिड़े कार्यकर्ता

संचार जगत



भीलवाड़ा। राजस्थान में जिला प्रमुख चुनाव को लेकर प्रदेशभर में सियासी सरगर्मियां तेज रही। 37 जिलों में जिला प्रमुख और प्रधान चुनने की प्रक्रिया के बीच कई जगहों पर राजनीतिक टकराव देखने को मिला। इस बीच भरतपुर और भीलवाड़ा में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। दोनों जगह जमकर नारेबाजी हुई। भीलवाड़ा में तो कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की तक हो गई। यहां जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई, जब अंदर प्रवेश को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। कलेक्ट्रेट में एंट्री को लेकर दोनों दलों के समर्थकों के बीच काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के सामने नारेबाजी भी की। भरतपुर में भी जिला प्रमुख चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं, शपथ लेने वाले कांग्रेस सदस्यों को घेराबंदी के बीच कलेक्ट्रेट सभागार तक ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी गरमा गया। कांग्रेस सदस्यों को सुरक्षा घेरे में सभागार तक पहुंचाया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा रही और राजनीतिक नारेबाजी का दौर चलता रहा। चुनाव के दौरान जिला मुख्यालयों पर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। कई जिलों में उम्मीदवारों की जीत को लेकर दोनों दलों के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। ऐसे में मतदान से पहले और मतदान के दौरान भी राजनीतिक माहौल गरमाया रहा।

हाईकोर्ट ने सीएमआरएल मामले की जांच पर रोक बढ़ाई

संचार जगत



कोच्चि। केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीणा और दामाद एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद रियास के खिलाफ सीएमआरएल-एक्सालॉजिक कथित भुगतान मामले में आगे की जांच पर रोक 15 दिसंबर तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति स्याम कुमार वी.एम. की खंडपीठ ने 26 अक्टूबर को जारी अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज एफआईआर में आगे की जांच पर रोक जारी रखी।

वृंदा कोठारी के नेतृत्व में नई दिल्ली की एक विशेष दिवसीय यात्रा का आयोजन

बोर्डरूम से आगेः फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की संसद यात्रा नई दिल्ली

संचार जगत





जयपुर। नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक जागरूकता और संस्थागत सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर ने अपनी चेयरपर्सन वृंदा कोठारी के नेतृत्व में 23 नवंबर 2026 को नई दिल्ली की एक विशेष दिवसीय यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा के अंतर्गत सदस्याओं को भारतीय संसद के दोनों सदनों - लोकसभा एवं राज्यसभा - का निर्देशित भ्रमण कराया गया। यात्रा का विशेष आकर्षण राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ आयोजित एक विशेष संवाद सत्र रहा। इस प्रतिनिधिमंडल में फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की 90 सदस्याओं ने भाग लिया। यह यात्रा सभी के लिए ज्ञान, अनुभव, संवाद और सामूहिक सहभागिता का एक यादगार अवसर बनी। जयपुर के केसरगढ़ से प्रातः रवाना हुआ यह प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर पहुँचा। यहाँ सदस्याओं को लोकसभा एवं राज्यसभा के ऐतिहासिक और आधुनिक सदनों का भ्रमण करने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक विरासत, संसदीय परंपराओं और विधायी प्रक्रियाओं को करीब से जाना और समझा। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण राज्यसभा के माननीय उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के साथ आयोजित विशेष संवाद सत्र रहा। अपने संबोधन में उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति, समाज में उनकी बदलती भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के महत्व तथा देश के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत विकास में महिलाओं के बढ़ते योगदान को रेखांकित किया।इस विशेष संवाद के दौरान हरिवंश ने भारत के उल्लेखनीय आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन पर भी अपने विचार साझा किए। महिला उद्यमियों, व्यवसाय जगत की नेतृत्वकर्ताओं और युवा नवाचारकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के भविष्य को आकार देने में महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और सतत नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। अपने संबोधन के समापन में युवाओं को एक प्रेरणादायक संदेश देते हुए श्री हरिवंश ने कहा कि स्थायी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता।

उन्होंने युवाओं को अनुशासन, निरंतर प्रयास, धैर्य और ईमानदारी के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। साथ ही, उन्होंने भारत के तेजी से विकसित होते स्टार्टअप परिवेश और एक सतत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ती गति पर गर्व व्यक्त किया। इस संवाद ने फिक्की फ्लो की सदस्याओं को संसदीय नेतृत्व के साथ सीधे विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। महिला उद्यमिता, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बदलती भूमिका और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए अवसरों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

वृंदा कोठारी, चेयरपर्सन ने कहाः फिक्की फ्लो जयपुर में हमारा उद्देश्य महिलाओं को केवल सफल व्यवसायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में ही नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में जागरूक और सक्रिय भागीदार के रूप में भी सशक्त बनाना है।

कश्मीर घाटी के बच्चों ने राज्यपाल से की मुलाकात



संचार जगत

जयपुर। सामाजिक चेतना अभियान के तहत कश्मीर घाटी के 25 बच्चों ने लोकभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। भारत दर्शन यात्रा के तहत राजस्थान यात्रा पर आए इन बच्चों से संवाद करते हुए राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत विविधता में एकता लिए है। उन्होंने कश्मीर के इतिहास, संस्कृति और उसे भारत से अलग करने के षड्यंत्रों की चर्चा करते हुए कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव के साथ राष्ट्र विकास में सभी समान भूमिका निभाएं। इसी से विकसित भारत के स्वप्न को हम साकार कर पाएंगे।

राजस्थानी भाषा के विद्वान प्रो. गोपाल सिंह राठौड़ का निधन

संचार जगत



उदयपुर। शिक्षा, साहित्य एवं राजस्थानी भाषा के विद्वान प्रो. गोपाल सिंह राठौड़ का निधन हो गया है। वे शिक्षाविद्, विद्वान साहित्यकार एवं अंग्रेज़ी भाषा के प्राध्यापक थे। वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़ गए है। उदयपुर के प्रतिष्ठित बी.एन. कॉलेज में उपप्राचार्य सहित विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन्होंने शिक्षा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। राजस्थानी भाषा के संवर्धन, संरक्षण एवं प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए उन्होंने साहित्य लेखन, शोधपरक विचार-विमर्श एवं अनेक संगोष्ठियों में योगदान दिया। वे मातृभाषा के प्रति उनकी निष्ठा, विद्वत्ता एवं साहित्यिक अवदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे। प्रो. गोपाल सिंह राठौड़, डॉ. आदित्य नाग के श्वसुर थे। उनका स्नेहिल सान्निध्य, आत्मीयता एवं गरिमामय व्यक्तित्व सदैव हमारी स्मृतियां हमेशा याद रहेगी।

सुप्रिया सुले ने मुख्यमंत्री बनने की अफवाहों को किया खारिज

संचार जगत



कराड। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया में चल रही उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि पार्टी प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन देने और संसद में आने वाले परिसीमन विधेयक का समर्थन करने के बदले उनके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद मांगा है। महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण को उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद सुप्रिया सुले ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बदलती चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अफवाहें थीं कि उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है और अब मुख्यमंत्री पद की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है। मेरे साथ ऐसा अन्याय न करें। 2014 से ही मैं मुख्यमंत्री बनती आ रही हूं। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बस इस बात का दुख है कि कोई मुझसे गंभीरता से उन नीतिगत कार्यों के बारे में नहीं पूछता, जिनके लिए मुझे संसद में चुनकर भेजा गया है।

बाजार में गिरावट पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर कसा तंज

संचार जगत



मुंबई। शिवसेना यूबीटी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सोमवार को शेयर बाजार में आई भारी गिरावट के बाद पार्टी ने सवाल उठाया कि जब अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की ताकत बढ़ रही है, तो आम निवेशकों को भारी नुकसान क्यों हो रहा है। दरअसल, सोमवार को बाजार में बड़ी गिरावट आई थी, उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट का एशिया पावर इंडेक्स 2026 जारी हुआ था। इसमें भारत को एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में तीसरे स्थान पर रखा गया है और पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद क्षेत्र का दूसरा सबसे प्रभावी नेता बताया गया है। शिवसेना के ठाकरे गुट ने इसी अंतर पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि, प्रधानमंत्री का प्रभाव कहां चला गया और ये तरक्की आखिर किसकी है?

सैलजा ने खिलाड़ियों की के लिए जताई चिंता

संचार जगत



चंडीगढ़। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में खिलाड़ियों को समय पर पुरस्कार राशि, खेल किट और यात्रा भत्ता नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार खिलाड़ियों के सम्मान में बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो करती है, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाती। केवल घोषणाओं से खिलाड़ियों का सम्मान नहीं होता, इसके लिए उन्हें समय पर उनका हक देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोहतक में आयोजित अंडर-14 राज्य स्तरीय स्कूली योग एवं हॉकी प्रतियोगिताओं के डेढ़ माह बाद भी 72 पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि नहीं मिली है।

जेजेएम घोटाले में सुबोध अग्रवाल को मिली

संचार जगत



नई दिल्ली। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सुबोध अग्रवाल के साथ तत्कालीन चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और एमपी मीणा को भी जमानत दे दी।

तीनों आरोपी पिछले करीब सात महीने से जेल में बंद थे। इस मामले में इससे पहले पूर्व मंत्री महेश जोशी को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले त्वरित सुनवाई के अधिकार को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को जमानत देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद जेजेएम घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद तीनों अधिकारियों को राहत मिली है। मामले में आगे ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल को 9 अप्रैल को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में थे।

सुबोध अग्रवाल ने जमानत के लिए पहले राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

मदन राठौड़ ने कहा 2028 के विधानसभा चुनाव में फिर बनेगी भाजपा सरकार

कांग्रेस का हंगामा सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा हुआ साबित, माफी मांगे कांग्रेस : मदन राठौड

संचार जगत



जयपुर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को जिला प्रमुख के चुनाव में 10 जिलों में पार्टी का जिला प्रमुख बनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरी है, भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए जनता के जनादेश को विनम्रता से ?स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि आगामी दो वर्षों में और अधिक गति से राजस्थान की सेवा की जाएगी और 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि पंचायती राज के चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को अपने उस झूठे प्रोपेगेंडा पर जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने परिसीमन पर झूठ बोला, ईवीएम को बदनाम किया, हमारी चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाए गए। ये सब अब जनता के समझ में आ गया है, इसलिए कांग्रेस को जनता से और भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के परिणाम विधानसभा के चुनाव परिणाम नहीं होते। अब तक हुए पंचायती राज चुनाव परिणामों के आधार पर भी ये बात साबित होती है कि पंचायती राज चुनावों में किसी पार्टी की जीत विधानसभा चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती है। राजस्थान की जनता ने पांच साल के लिए हमें जो सेवा का अवसर दिया है, उसी के अनुरूप अगले दो वर्ष हम पूरी प्रमाणिकता और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने भरतपुर चुनाव को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की थी, वह अराजकता को फैलाने वाली थी। यह जिम्मेदार राजनेता का बयान नहीं हो सकता। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह संयम का परिचय दिया उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की कथनी और करनी में भेद है, चूरू में भाजपा की जीत पर कुछ कहते है और ब्यावर में कांग्रेस की जीत पर उनका बयान बदल जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायती राज चुनाव में मिली क्षणिक सफलता से अपच का शिकार हो गई है। जिसके कारण कांग्रेस के नेता बोराए घुम रहे है। कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुशासन की बात करना बेमानी सा लगता है। सुशासन और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। पिछले कांग्रेसराज में सरकार होटल में चलती हुई जनता ने देखी थी, और उसका परिणाम भी 2023 में कांग्रेस ने भुगता है। इसलिए मेरी सलाह है कि कांग्रेस अहंकार में ना आए, भाजपा के कार्यकर्ता पूरी क्षमता से 2028 चुनाव में जवाब देंगे।

प्रभारी, भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग

मतदाता पंजीयन के लिए क्लस्टर कैंप आयोजित

संचार जगत



बहरोड़। बहरोड़ स्थित श्री धर्मचंद गांधी जैन राजकीय महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता एवं पंजीयन के लिए विशेष क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा विद्यार्थियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना था। इस मौके पर छात्रों को बताया गया कि लोकतंत्र की मजबूती में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस विशेष शिविर की शुरुआत की गई है। विद्यार्थियों से मतदाता पंजीयन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने तथा महाविद्यालय में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करवाने का आह्वान किया। कैंप के दौरान बड़ी संख्या में नव मतदाताओं से मौके पर ही फॉर्म-6 भरवाए गए और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

आठवले ने भाजपा-अकाली के एक साथ होने को बताया गेमचेंजर



मुंबई। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी-अकाली दल के फिर से एक साथ आने को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने गेमचेंजर बताया है। उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार से नाराज पंजाब की जनता अब भाजपा की ओर देख रही है और गठबंधन के दम पर राज्य में सरकार बन सकती है। आठवले ने कहा कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल और भाजपा हमेशा लंबे समय तक एक साथ रहे थे और उनकी सत्ता भी लंबे समय तक रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही थी

दो मुख्यमंत्रियों ने शांति, विकास और सहयोग पर की चर्चा

संचार जगत



इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच शांति, विकास और आपसी सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इंफाल के बाबूपाड़ा स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई इस बैठक में दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच शांति, विकास और आपसी विश्वास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने बताया कि हमने दोनों राज्यों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक सार्थक बैठक की। इस बैठक में मणिपुर के उपमुख्यमंत्री लोसी डिखो और एनपीएफ के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अवांगबो न्यूमाई भी शामिल हुए। 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में नागा पीपुल्स फ्रंट के पांच विधायक हैं और यह राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी पार्टी है।

मणिपुर के उपमुख्यमंत्री लोसी डिखो, एनपीएफ के एक वरिष्ठ नेता भी हैं।

छात्राओं ने सीखे योग और प्राणायाम के गुर



संचार जगत

जयपुर। कानोड़िया पी.जी. महिला महाविद्यालय के वेलनेस क्लब द्वारा योगा फॉर एवरी डे एंड एवरी वन विषय पर योग सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य दैनिक जीवन में योग के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग को जीवनशैली का अभिन्न अंग बनाने हेतु प्रेरित करना है। प्रतिभागियों को योग के विभिन्न अभ्यासों एवं उनके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान दी गई। सत्र में छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को नियमित योगाभ्यास, शारीरिक सक्रियता, मानसिक शांति एवं तनाव प्रबंधन के महत्व से अवगत कराया गया। इसमें दैनिक जीवन में सरल योगासन एवं प्राणायाम को अपनाने के व्यावहारिक तरीकों पर भी प्रकाश डाला गया। इस अवसर रक वक्ताओं ने योग एवं स्वस्थ जीवनशैली को दैनिक दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मकर संक्रांति के त्योहार से पहले पुलिस ने 1500 चरखी चाइनीज मांझा जब्त किया



संचार जगत

सीकर। मकर संक्रांति के त्योहार से पहले पुलिस ने चाइनीज मांझे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1500 चरखी चाइनीज मांझा जब्त किया है। जब्त मांझे की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपये बताई गई है। यह मांझा शहर के विभिन्न इलाकों में बिक्री के लिए पहुंचाया जाना था। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है। कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से इस मामले की सूचना मिली थी। पुलिस की विशेष टीम को रामलीला मैदान के पास सड़क किनारे कार्टूनों का ढेर मिला। तलाशी लेने पर सभी 25 कार्टूनों में चाइनीज मांझा पाया गया। प्रत्येक कार्टून में 60 चरखी थीं। इस प्रकार कुल 1500 चरखी अवैध चाइनीज मांझा जब्त कर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। मकर संक्रांति के दौरान इसके उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस द्वारा अवैध मांझे के कारोबार पर निगरानी रखी जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति और बिक्री की योजना को समय रहते कार्रवाई कर रोका गया।

बॉल कॉर्पोरेशन की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया

एडवांस्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बन रहा मेरठ : सीएम योगी

संचार जगत



लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर में वैश्विक दिग्गज बॉल कॉर्पोरेशन की नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का शिलान्यास किया। 2 हजार 900 करोड़ से अधिक के निवेश से स्थापित होने जा रही एल्युमिनियम बेवरेज कैन की इस विश्वस्तरीय इकाई के भूमिपूजन अवसर पर मुख्यमंत्री ने बॉल कॉर्पोरेशन की टीम का आभार जताते हुए कहा कि यह प्लांट आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर योगी ने मेरठ के औद्योगिक कायाकल्प पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के लिए एक एंकर यूनिट के रूप में कार्य करेगी, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही स्थानीय एमएसएमई, पैकेजिंग सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और रीसाइक्लिंग पार्टनर्स के लिए भी व्यापार के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने बताया कि बीते साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट में 7 लाख 50 हजार करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं।

लखनऊ में राजनीतिक सरगर्मियां रहेंगी तेज



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज राजधानी लखनऊ में ओवैसी और चंद्रशेखर अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभा संबोधित करेंगे।

आज कांग्रेस की भी रैली है। यूपी में गठबंधन के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर रमाबाई अम्बेडकर मैदान में आयोजित होने वाली आजाद समाज पार्टी की रैली में एक साथ नजर आएंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभा को संबोधित करेंगे। वे पार्टी द्वारा आयोजित संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इन कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

स्वामित्व, प्रकाशक एवं संपादक : अवंतिका राठौड़ - पी.के. प्रिंटर्स एंड स्टेशनर्स, 31, राम मंदिर के पास, पटेल नगर, 22 गोदाम, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। कार्यालय : जे-17, रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर। संपर्क : 0141 463 7668
ई-मेल : sancharjagat@gmail.com| आरएनआई नं. : RAJHIN/2014/55262 समाचार चयन के लिए पीआरबी अधिनियम के तहत जिम्मेदार। न्यायाधिकार क्षेत्र : जयपुर महानगर।